

मणिपुर में हिंदी का परिदृश्य

-डॉ. आर. के. मोबी सिंह

मणिपुर में हिंदी की वर्तमान स्थिति को जानने-समझने के लिए यहाँ के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में हिंदी अध्ययन अध्यापन की स्थिति का पर्यवेक्षण करना जरूरी है। यहाँ के कानन देवी-विद्यालय, आर. के. सनातोम्बी विद्यालय, सैनिक स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय जैसे सी.बी. एस. ई. से सम्बद्ध विद्यालयों में से सिर्फ केन्द्रीय विद्यालय ही एक मात्र ऐसा स्कूल है जिसमें दसवीं कक्षा तक हिंदी विषय का अध्ययन करना अनिवार्य है। जबकि अन्य सी.बी.एस.ई. के स्कूलों में सिर्फ आठवीं कक्षा तक ही हिंदी पढ़ाई जाती है। मणिपुर के सरकारी एवं निजी स्कूलों में भी आठवीं कक्षा तक ही हिंदी का अनिवार्य शिक्षण होता है और आगे की कक्षाओं में यह अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। मणिपुर के विद्यालयों में कक्षा आठ के बाद हिंदी शिक्षण की अनिवार्यता का समाप्त होना यहाँ के छात्र-छात्राओं में हिंदी के प्रति अरुचि का कारण बनता है। क्योंकि छात्रों के मन में यह बात घर कर जाती है कि हिंदी सिर्फ आठवीं कक्षा तक ही पढ़नी है आगे नहीं। जिससे कुछेक छात्रों को छोड़कर शेष छात्र किसी तरह आठवीं की परीक्षा पास करके हिंदी से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। बच्चों की यही मानसिकता हिंदी भाषा के प्रति अरुचि पैदा करती है जो एक सोचनीय विषय है। बच्चों के साथ ही अविभावक भी बच्चों में हिंदी के अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करने में योगदान नहीं देते। इस कारण आठवीं कक्षा तक के छात्रों में हिंदी ही एक ऐसा विषय रहता है जिसमें छात्र-छात्राएँ बहुत कम अंक लेकर उत्तीर्ण होते हैं या कुछ छात्र अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं। आठवीं कक्षा तक, जहाँ हम हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाते हैं अगर इसकी यह स्थिति है तो आगे की कक्षाओं- नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं में जहाँ हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है उसकी क्या दशा होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। टी.जी. हायर सेकेन्डरी स्कूल, जॉनोस्तोन हायर सेकेन्डरी स्कूल और सी.सी. हाथर सेकेन्डरी जैसे स्कूलों में बारहवीं कक्षा तक हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। लेकिन इन स्कूलों में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या न के बराबर रहती है। काउन्सिल ऑफ हायर सेकेन्डरी एजुकेशन, मणिपुर की एक रिपोर्ट के अनुसार विगत वर्ष 2017 के सत्र में बारहवीं परीक्षा के परिणाम में सिर्फ 16 छात्र-छात्राओं ने हिंदी की परीक्षा दी और उनमें से 12 छात्र-छात्राओं ने ही परीक्षा उत्तीर्ण की।

महाविद्यालयों के स्तर पर डी. एम. कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जी.पी. वूमन कॉलेज, प्रेसीडेन्सी कॉलेज जैसे सरकारी महाविद्यालयों के साथ लिबरेल कॉलेज, एस. के. वूमन कॉलेज जैसे निजी कॉलेजों में बी.ए. ऑनर्स (हिंदी) या बी. ए. जनरल (हिंदी) पाठ्यक्रम में अध्ययन अध्यापन की सुविधाएँ हैं लेकिन पिछले कुछ सालों की तुलना में आजकल इन कॉलेजों में हिंदी अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दयनीय है। डी.एम. कॉलेज ऑफ आर्ट्स जिसे मणिपुर का प्रीमियर कॉलेज माना जाता है वहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में बी.ए. पाठ्यक्रम में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है।

कोई भी बी.ए., बी.ए.सी. उत्तीर्ण छात्र राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, वर्धा जैसी संस्थाओं से 'हिंदी रत्न' परीक्षा उत्तीर्ण करके मणिपुर विश्वविद्यालय में एम.ए. हिंदी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं लेकिन महाविद्यालयों में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर हिंदी विषय के साथ इन्टरमीडियट की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही बी.ए. ऑनर्स में हिंदी ले सकते हैं। इस कारण भी महाविद्यालयों में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। दूसरी ओर मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एम.ए. पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी दिनोंदिन घटती जा रही है। यहाँ पर महाविद्यालयों से बी.ए. ऑनर्स (हिंदी) उत्तीर्ण दो या तीन छात्र ही प्रवेश लेते हैं। शेष छात्र 'हिंदी रत्न' उत्तीर्ण करके एम.ए. हिंदी पाठ्यक्रम में प्रवेश करते हैं। फिर भी वहाँ पर एम.ए., हिंदी पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित आधी से भी कम सीटें भर पाती हैं। मणिपुर में हिंदी की अच्छी प्रगति हो इसका बड़ा दायित्व यहाँ के हिंदी प्रचारकों एवं अध्यापकों पर निर्भर है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मणिपुर में राजकीय स्तर पर हिंदी प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले गए हैं। राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान एवं राजकीय हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय ऐसी संस्थाएँ हैं जिनमें हिंदी माध्यम से अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। ताकि हिंदी की विकास गति में तीव्रता आए और हिंदी के प्रति लोगों में अत्यधिक रुचि उत्पन्न हो। फिर भी हिंदी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इम्फाल की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर प्री- सर्विस एवं इन- सर्विस दोनों को मिलाकर हर वर्ष में 5. सीटें निर्धारित हैं। जहाँ पर नामांकन करने वाले स्थानीय छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष घट रही है। जबकि बाहर से आने वाले हिंदीभाषी छात्रों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थिति भी कुछ इसी तरह की है जहाँ वर्तमान वर्ष अर्थात् 2017 की प्रवेश परीक्षा में निर्धारित सीटें भी नहीं भर पाई हैं।

यहाँ पर संस्थागत स्तर पर भी हिंदी का प्रचार-प्रसार हो रहा है। मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इम्फाल की स्थापना 1950ई. में हुई। वर्तमान समय में समिति के अन्तर्गत 65 परीक्षा केन्द्र, 22 शिक्षण केन्द्र, 24 विद्यालय तथा 21 महाविद्यालय संचालित हैं। इस संस्था का दावा है कि अब तक इनके द्वारा लाखों की संख्या में मणिपुर के लोग हिंदी सीख चुके हैं, पर आजकल यहाँ भी छात्रों की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है।

3835 मणिपुर राज्य की एकमात्र स्वैच्छिक हिंदी संस्था मणिपुर हिंदी परिषद् की स्थापना 1953ई. में हुई। मणिपुर हिंदी परिषद् की स्थिति भी इस दृष्टि से संतोषजनक नहीं है। वहाँ पर भी प्रत्येक वर्ष पढ़ने वाले छात्रों की संख्या घट रही है।

आज मणिपुर में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या दिन-ब- दिन कम होती जा रही है। यह एक विचारणीय विषय है। हम हिंदी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है या हिंदी हमारी सम्पर्क भाषा है। यह मात्र कहने और सुनने की बात है, पर इसके पीछे एक अलग ही कारण है कि हम हिंदी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमारे भविष्य की सम्भावनाएँ जुड़ी हैं। हम इसलिए हिंदी पढ़ते हैं ताकि बाद में कुछ लाभ

मिले और हिंदी सीखकर हमें नौकरी मिले, वह हमारी जीविका का साधन बने। लेकिन आजकल मणिपुर में हिंदी पढ़कर भविष्य की सम्भावनाएँ कम दिखाई दे रही हैं। यहाँ हिंदी पढ़कर रोजगार के अवसर न के बराबर हैं। जो थोड़े बहुत छात्र-छात्राएँ हिंदी भाषा और साहित्य में उच्च अध्ययन करके निकलते हैं उनके लिए पिछले कई वर्षों से हिंदी शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर शिक्षण करने की सम्भावनाएँ लगभग समाप्त प्रायः हैं। मणिपुर के स्कूलों, कॉलेजों व पर्यटन क्षेत्र में हिंदी को लेकर रोजगार की सम्भावनाएँ प्रायः नगण्य है। मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से वर्ष 2009ई. में हिंदी का एक नियमित प्रोफेसर नियुक्त किया गया। तब से आजतक हिंदी में किसी पद की नियुक्ति नहीं हुई है। आकाशवाणी इम्फाल में एक नियमित अनुवादक पद की नियुक्ति सन् 1998ई. को हुई थी। तब से यहाँ भी आजतक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। वर्ष 2011ई. में 175 हिंदी प्राइमरी टीचरों और 49 हिंदी ग्रेजुएट टीचरों की रेगुलर पोस्ट पर नियुक्ति के बाद आजतक मणिपुर शिक्षा विभाग मौन है। मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010ई. में इस संस्था से 1490 लोगों ने अलग अलग कक्षाओं में परीक्षा दी और 2011 में परीक्षा देने वालों की संख्या 3835 थी। एक ही साल में 2345 छात्र-छात्राओं की बढ़ोतरी का एकमात्र कारण है मणिपुर सरकार की ओर से उस वर्ष कुछ हिंदी अध्यापकों के रिक्त पदों में भर्ती की प्रक्रिया थी।

गत वर्षों में मणिपुर में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कम होने का दूसरा कारण यह भी है कि हिंदी द्वारा अन्य विषयों की बराबरी न कर पाना। मणिपुर में अन्य विषय जैसे अंग्रेजी, गणित, भौतिकी आदि में जो निजी या सरकारी नौकरी की प्राथमिकता है वह हिंदी विषय वालों को नहीं मिलती। मणिपुर के स्कूलों में आठवीं कक्षा तक हिंदी अनिवार्यता होने के कारण अन्य विषयों की तुलना में हिंदी छात्रों की संख्या बहुत ही कम है। जब हिंदी छात्रों की संख्या कम है. तो स्वाभाविक ही हिंदी अध्यापकों की जरूरत भी कम ही होगी। अन्य विषयों के छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक होने के कारण उसी विषय से सम्बन्धित अध्यापकों को कहीं- न-कहीं रोजगार मिल जाता है चाहे वे प्राइवेट स्कूल में हो या प्राइवेट ट्यूशन में। आजकल मणिपुर में कई प्राइवेट कम्पनियाँ खुलने लगी हैं। कई नए-नए फर्म आने लगे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी अधिक मात्रा में कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है। कई बैंकों में भी कर्मचारियों की भर्ती हो रही है। इन रिक्त पदों के लिए हिंदी बोलने और जानने की माँग भले ही न की गई हो, लेकिन हर प्रतिभागी को अंग्रेजी जानना एवं बोलना अनिवार्य बताया गया है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ हिंदी की तुलना में अंग्रेजी भाषा को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है।

हिंदी हमारे देश की सम्पर्क भाषा है। मणिपुर राज्य राजभाषा प्रयोग के 'ग' क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जिसके कारण यहाँ पर हिंदी पूर्णरूप से सम्पर्क भाषा नहीं बन पाई है। यह भी मणिपुरी निवासियों में हिंदी के प्रति अरुचि उत्पन्न होने का एक मुख्य कारण रहा है। भारत के किसी भी क्षेत्र में दो अलग- अलग अहिंदीवासी हिंदी भाषा के माध्यम से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। हिंदी जानने वाले कोई बंगाली, कोई असमिया, कोई पंजाबी हिंदी भाषा द्वारा अपना काम निकाल लेते हैं। वे सीखी हुई हिंदी का कुछ तो लाभ उठाते हैं। लेकिन यह स्थिति मणिपुर में नहीं है। यहाँ हिंदी जानने वाला कोई मणिपुरी अंग्रेजी में बात

करते समय अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है। मणिपुर में आने वाले बाहरी लोग भी यहाँ अंग्रेजी बोलना ही अधिक पसन्द करते हैं जबकि उन्हें पता होता है कि सामने वाले को हिंदी बोलनी आती है और तो और मणिपुर में रहने वाले दो अलग-अलग समुदाय के लोग भी अंग्रेजी भाषा को सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं जबकि वे दोनों हिंदी की अच्छी जानकारी रखते हैं। इस तरह यहाँ पर उनको हिंदी भाषा जानने और न जानने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।

मणिपुर के स्कूल-कॉलेजों की स्थिति को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मणिपुर में हिंदी का भविष्य संतोषजनक नहीं है। एक तरफ मणिपुर में सरकारी या निजी संस्थाओं में औपचारिक ढंग से हिंदी सीखने वालों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर के कई आदमी चाहे बच्चे हो या बूढ़े अपनी अपनी आवश्यकतानुसार अनौपचारिक तौर से हिंदी सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और दिन ब दिन इन लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। शिडजमें में स्थिति आर. के. हिंदी कोचिंग सेन्टर में 45 दिनों के एक कोर्स में कम-से-कम 20 से 25 छात्र-छात्राएँ हिंदी बोलचाल सीख रहे हैं तथा पिछले पाँच सालों में यहाँ से लगभग दो हजार से ऊपर छात्र-छात्राएँ हिंदी सीखकर लाभान्वित हो चुके हैं।

मणिपुर में हिंदी की इस दयनीय स्थिति में सुधार के लिए छात्र-छात्राओं में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए सरकार को हिंदी अध्ययन-अध्यापन के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए, जिनमें स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने की व्यवस्था के साथ हिंदी अध्यापकों की पर्याप्त उपलब्धता भी शामिल है। सरकार हिंदी पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को आवश्यक अनुदान दे ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। हिंदी भाषा सम्बन्धित भविष्य की सम्भावनाओं को भी भारत सरकार एवं मणिपुर सरकार ध्यान में रखे। उनको हिंदी के रिक्त पदों की पूर्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। आवश्यकतानुसार नए नए हिंदी से सम्बन्धित पदों की भी रचना करना जरूरी है। मणिपुर के कुछ संस्थानों को भारत सरकार से हर वर्ष अनुदान मिलता है। लेकिन यह अनुदान की राशि बहुत कम है, ऊपर से कई कई साल तक एक ही अनुदान राशि मिलती रहती है। मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इम्फाल को गत तीन वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15, 2015-16 में एक ही धनराशि (11, 51, 150) प्राप्त हुई। इस महाविद्यालय में कार्यरत एक अध्यापक को 1500 मासिक वेतन मिलता है जो बहुत कम है, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथ ही, सरकार को स्थानीय कानून व्यवस्था के प्रति उचित ध्यान देना चाहिए जिससे अधिक संख्या में बाहरी पर्यटक, व्यापारी या राजनेता लोग मणिपुर में आएँ तथा हिंदी में शिक्षित लोगों को रोजगार मिले। मणिपुर में कई सालों से सिनेमाघरों में हिंदी फिल्मों एवं सार्वजनिक जगहों पर हिंदी गीतों के प्रसारण पर कई पाबन्दियाँ रखी गई हैं, जिनको धीरे-धीरे समाप्त किया जाना चाहिए।

अन्ततः हिंदी का प्रचार-प्रसार करने में मणिपुर एक उचित राज्य माना जा सकता है। समूह 'ग' क्षेत्र के राज्यों में मणिपुर ऐसा एक मात्र राज्य है जहाँ हिंदी बाज़ारी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। मणिपुर के बाहर जाकर बहुत सारे लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा वहाँ पर वे हिंदी सीखकर वापस आ रहे हैं। इससे भी हिंदी का प्रसार हो रहा है। मणिपुर में हिंदी का भविष्य उज्ज्वल हो। इसके लिए राज्य

सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा हिंदी को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। साथ ही, यहाँ के निवासियों को राष्ट्र की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए हिंदी के प्रति रुचि प्रदर्शित करनी होगी। तभी मणिपुर में हिंदी की दशा में सुधार होगा एवं उसके प्रचार प्रसार को उचित दिशा प्राप्त होगी।

(C) महिष पत्रिका मणिपुर हिंदी परिषद, इन्फाल, जून 2017ई.